F. No. 1304 (H.O.)

Karnataka Bank Ltd.

Estd : 1924 CIN : L85110KA1924PLC001128

Regd. & Head Office
P.B. No. 599, Mahaveera Circle
Kankanady, Mangalore – 575 002

Phone : 0824 - 2228222 Fax : 0824-2225588
Website : www.karnatakabank.com
email : info@ktkbank.com

14.12.2016 SECRETARIAL DEPARTMENT
HO:SEC:483 :2016-2017

The General Manager,
Bombay Stock Exchange Limited
Corporate Relationship Dept
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI-400 001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange Of India Limited.,
Exchange Plaza,C-1, Block G
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E),
MUMBAI-400 051

Dear Sir,

Re: Disclosure under Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015- Sharing the copy of advertisement of 'Basis of Allotment' of Rights Equity Shares published in the newspapers.

******

With reference to the above, in terms of Regulation 30(6) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Schedule III, Para A(12), and Regulation 66 of SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements Regulations, 2009, we enclose herewith the copy of newspaper publications made regarding the 'Basis of Allotment' of Rights Equity Shares of the Bank for your information.

Thank You,

Yours faithfully,

COMPANY SECRETARY

संवेदनशील सूचनाओं के प्रबंधन पर कंपनी जगत चिंतित

टाटा विवाद के बाद भेदिया कारोबार के नियमों का उल्लंघन टालने के लिए निदेशक मंडल सतर्कता भरा रुख अपना रहे हैं

पवन बुरगुल
मुंबई, 13 दिसंबर

टाटा-मिस्त्री विवाद के बाद कॉरपोरेट संवेदनशील सूचनाओं का प्रबंधन भारतीय कंपनी जगत के लिए चिंताजनक मसला बन गया है। भेदिया कारोबार के रद्द कानून के उल्लंघन का दर बोर्डरूम और संबंधित पक्षकारों के बीच सूचनाओं के प्रवाह का असल दायरा रहा है, जहां तीन से सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मामले में। पहले एमटासॉफ्ट के निदेशक मंडल के सदस्यों को तगड़ा भेदिया कारोबार नियम तोड़ने के दौरान अपने निजी प्रयोजनों से संबंधित सौदों का पता चला था। हालांकि यह मामला सेबी-कानूनी नहीं है, लेकिन कंपनियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इससे यह कानून का उल्लंघन किया जाए।

कानून का अनुपालन सुनिश्चित कर रहीं कंपनियां

- पहले एमटासॉफ्ट के निदेशक मंडल के सदस्यों की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला लिए जाने के दौरान अपने वित्तीय प्रयोजनों से संबंधित सौदों का पता चला था। हालांकि यह मामला सेबी-कानूनी नहीं है, लेकिन कंपनियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि इससे यह कानून का उल्लंघन किया जाए
- अब एमटासॉफ्ट को अहसास हुआ है कि प्रबंधक की तरफ से ऐसी सूचनाएं मॉनसून के मौसम में कंपनी सीक्रेट्स फॉरेबार कानून के दायरे में आ सकती हैं
- इन दिनों वे अपने निदेशक मंडलों को बोर्ड का एथाइनाइज के जरिए रुपये करने के लिए प्रोएक्टिव कर रहे हैं



कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि संवेदनशील सूचनाएं भेदिये भर से संबंधित जानकार नहीं होना जब तक कि इस सूचना के जरिए कोई कारोबार का अनुचित लाभ नहीं उठाया जा रहा हो।

सेबी के पूर्व अधिकारी व सुबेन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर सुबिर सहाय ने कहा, भेदिया कारोबार कानून में लाभ का अधिकार परिभाषित नहीं है। किसी सूचना भेजने वाली भी अनाम नहीं रह है और यह भेदिया कारोबार कानून में भी यह एक अपराध है पर इसकी भी पहचान है। सेबी के नियम के मुताबिक, अज्ञातकालीन कीमत संबंधी संवेदनशील सूचना सबसे के साथ जानने के अधिकार के मुताबिक से सेबी को जानी चाहिए और संचालन में जुने किसी व्यक्ति को यह सूचना नहीं दी जानी चाहिए यहां कंपनी में उनको निर्धारित या प्रयोजक के साथ संबंध कैसे भी हों। कीमत संबंधी संवेदनशील सूचनाओं को एक ऐसी सूचना के तौर पर परिभाषित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी प्रतिभूति से संबंधित हो और इसके प्रकाशित होने पर उसकी कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है।

एक मुख्य ने कहा, इस प्रकार के भद्र एथाइनाइज को अहसास हुआ है कि प्रबंधक की तरफ से ऐसी सूचनाएं पंजाबी के लिए भेजने से कंपनी सीक्रेट्स भेदिया कारोबार कानून के दायरे में आ सकती है। इन दिनों वे अपने निदेशक मंडलों को बोर्ड का एथाइनाइज के जरिए रुपये करने के लिए प्रोएक्टिव कर रहे हैं।

एक कानूनी विशेषज्ञ ने कहा, खासतौर एथाइनाइज से सूचीबद्ध एथाइनाइज के मामले में भेदिये की अवधारणा के पृष्ठभाग जैसे मामले पर अंतिम फैसला लेने में पहले अपने निदेशी एथाइनाइज से संपर्क करना होता है। हालांकि निदेशी प्रयोजक ऐसे फैसले पर अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन वह अंतिम फैसला नहीं हो सकता। कंपनियां यह भेदिया कारोबार कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जीरो सहिष्णु की अवधारणा पर चल रही हैं।

सेबी के पूर्व अधिकारी व सुबेन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर सुबिर सहाय ने कहा, भेदिया कारोबार कानून में लाभ का अधिकार परिभाषित नहीं है। किसी सूचना भेजने वाली भी अनाम नहीं रह है और यह भेदिया कारोबार कानून में भी यह एक अपराध है पर इसकी भी पहचान है। सेबी के नियम के मुताबिक, अज्ञातकालीन कीमत संबंधी संवेदनशील सूचना सबसे के साथ जानने के अधिकार के मुताबिक से सेबी को जानी चाहिए और संचालन में जुने किसी व्यक्ति को यह सूचना नहीं दी जानी चाहिए यहां कंपनी में उनको निर्धारित या प्रयोजक के साथ संबंध कैसे भी हों। कीमत संबंधी संवेदनशील सूचनाओं को एक ऐसी सूचना के तौर पर परिभाषित किया गया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर किसी प्रतिभूति से संबंधित हो और इसके प्रकाशित होने पर उसकी कीमतों पर इसका असर पड़ सकता है।

संक्षेप में

एच 1 बी वीजा विवाद पर कार्रवाई मुमकिन

अमेरिका की एक संसदीय समिति ने संकेतों की आलोचना किया है कि अगर एच 1 बी वीजा का नियमन अधिनियमित नियमों के तौर में आता है तो अमेरिका के संयुक्त सीनेट के सदस्यों को कार्रवाई करने का संकेत मिल सकता है। 'अगर यह नियमन अधिनियमित नियमों में नहीं है,' अगर यह नियमन अधिनियमित नियमों में नहीं है, तो हमारा एक संसदीय समिति यह भी संकेत है कि उसमुद्दतियों यह कहे ने कि नियमित नहीं नियम के प्रतिनिधियों के अनुसार यही है और यह अमेरिका से यही कि अगले नियमों से उचित संशोधन को यहां से पेश नियमों के अनुसार हैं।' सेंटआलाप ने पीटि नियमों को आलोचना किया है कि इस आज के परिणाम से अनुपालन प्रक्रिया के तहत अगर कोरेस संबंद्ध नियमों से पालन नहीं करते हैं तो अमेरिका के वित्तीय एजेन्सुओं-अधिकृत व्यवसायी परिसभा शुरू हो सकते हैं।' भाषा

मार्च 2017 में भुगतान बैंक शुरू करेगी वोडाफोन इंडिया

सुरुर अर्चेट
मुंबई, 13 दिसंबर

दूरसंचार कंपनी वोडाफोन ने कहा है कि वह मार्च 2017 तक भुगतान बैंक शुरू करने की राह पर है। वोडाफोन को आरबीआई रिजर्व बैंक की तरफ से भुगतान बैंक शुरू करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है।

वोडाफोन दूरसंचार के पूरक निदेशक व मुख्य कार्याधिकारी सुनील सूद ने कहा, हम अंतिम चरण में हैं, लेकिन अभी तक हमारे अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। मार्च 2017 तक भुगतान बैंक शुरू करने के लिहाज से हमारी योजना पटरी पर है।

रिलायंस जियो इंफोकॉम लिमिटेड के प्रमुख मुकेश अंबानी ने हाल ही में कहा था कि उनकी कंपनी 31 दिसंबर, 2016 तक भुगतान बैंक शुरू करने की राह पर है। हालांकि अभी तक इसके अंतिम लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया है। मार्च 2017 तक भुगतान बैंक शुरू करने के लिहाज से हमारी योजना पटरी पर है।

रिलायंस जियो ने अगस्त 2016 में आरबीआई से 12 कंपनियों को भुगतान बैंक शुरू करने का लाइसेंस दिया था, जिसमें से जीत ने पुराने को लिहाज के बाद बैंक शुरू करने की योजना छोड़ दी। अभी तक एयरटेल ने भुगतान बैंक शुरू किया है। यह कंपनी दूरसंचार के क्षेत्र में मोटोरोला की प्रतिस्पर्धी है।

भुगतान बैंक को लाइसेंस नियमित सत्यापित के हाथों से दी गई है और इसे सिर्फ उच्च लाभांश करने की अनुमति दी गई है और यह बैंक ऋण नहीं दे सकता। इसे आम जनता से जमा को स्वीकार करने की अनुमति दी गई है और यह बैंक ऋण नहीं दे सकता। इसे आम जनता से जमा को स्वीकार करने की अनुमति दी गई है और यह बैंक ऋण नहीं दे सकता।

वोडाफोन का यह भी मानना है कि भुगतान बैंक को लाइसेंस के बाद उस परिसंपत्ति कंपनी को परिचालन और उपभोक्ता आधार का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी।

'एनएसईएल का कोई कानूनी दायित्व नहीं'

नेशनलिस्ट टेक्नोलॉजिक इंडिया लिमिटेड (जिसे अब 63 मून टेक्नोलॉजीज कहा जाता है), के उत्पीड़न इसीने खारिज दे कहा है कि अपने संघटकों पर पर्याप्त पोस्टकार्ड के खाते में ('एनएसईएल') का कोई कानूनी दायित्व नहीं है। ऐसे में कंपनी लगातार के मामले इस विवाद का अंतिम रूप नहीं होने हुई है। इस मामले के आदेश में कंपनी मालकों के संचालन द्वारा जमान विवाद का आदेश जारी किए जाने के बाद एनएसईएल ने मामले के लिए अदालत का रुख किया था। एनएसईएल ने कहा है कि उसका निवेश का आदेश इसके ग्राहकों के लिए नुकसानदेह है। एनएसईएल ने कहा है कि बोर्ड संचालन ने उसकी प्रतिभूति के लिए उसके निवेशकों के हितों को संरक्षण उपलब्ध होना। मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। भाषा

टाटा संस ने खरीदी टाटा मोटर्स की 1.73 फीसदी हिस्सेदारी

बीएस मंथलदास
मुंबई, 13 दिसंबर

टाटा बोर्ड के निदेशक मंडल से संचालन निवेशी को इजाजत देने के लिए होने वाली निवेशकों की महत्वपूर्ण बैठक से पहले टाटा संस ने इस क्रंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 3.75 फीसदी का इजाफा किया है। टाटा संस ने 466.33 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 5 करोड़ शेयर 2431 करोड़ रुपये में खरीदे। यह जानकारी पेशगत स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों से मिली। टाटा मोटर्स का शेयर आज इनसाइड पर 3.1 फीसदी की उछाल के साथ 470.3 रुपये पर बंद हुआ। यह शेयर 466.25 रुपये के उच्चतम पर खुला और 462.25 रुपये के निचले स्तर को छुआ। अंतिम हिस्सेदारी की खरीद के बाद टाटा मोटर्स में टाटा संस की हिस्सेदारी बढ़कर 34.73 फीसदी पर पहुंच गई।

टाटा संस ने 466 रुपये प्रति शेयर पर 5 करोड़ शेयर खरीदे, अब टाटा मोटर्स में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर 34.73 फीसदी हुई

हिस्सेदारी में बढ़ोतरी 22 दिसंबर को होने वाली कंपनी की असाधारण आम बैठक से पहले हुई है। साइरस मिस्त्री और तुलसी पांडेजा को निदेशक के पद से हटाने के लिए ईजीएम हो रही है। टाटा संस ने इस संबंध में प्रबंधन के पास नोटिस भेजी थी। नोटिस को प्रोमोटर ने हिस्सेदारी खरीद के लिए उपयोग 493.8 रुपये प्रति की भी और खरीदार का नाम नहीं बताया था।

ये शेयर कई निवेशकों से खरीदे गए और इनमें से ज्यादातर विदेशी निवेशक थे। जानकार के मुताबिक यह खरीदारी थी।

प्रमोटर समूहकंपनी के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के मुताबिक, संचालन को विदेशी निवेशक 218। फरवरी रखने के शुद्ध विकल्पवार थे। प्रोमोटरों ने कहा, 'व्यापार जैसा टाटा मोटर्स के केवे गए। हालांकि पर टाटा मोटर्स के 3,000 करोड़ रुपये के शेयर की खरीद-फरोख्त हुई। अनुकंपी की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा संस को 22 दिसंबर से पहले टाटा मोटर्स की असाधारण हिस्सेदारी लेनी थी। अधिग्रहण नोटिस के तहत प्रमोटर समूह अंतिम तारीख के दिन किसी कंपनी की पूरक फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर सकता है।

एसआर इंगवाले (जैसे निदेशक को इंडाल) के लिए सामान्य अनुज्ञा (10 फीसदी और एक शेयर) को समान होती है। हिस्सेदारी खरीद के बाद प्रमोटरों को सिस्मी से पहिलने का प्रस्ताव पारित करने को खरीद जरा संचालकों में 15.54 फीसदी समर्थन को इजाजत होगी।

प्रोमोटरों को देखने के बाद प्रबंधक समूह के पास टाटा मोटर्स में 34.16 फीसदी पारित अधिकार है, नहीं विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पास 26.7 फीसदी हिस्सेदारी है जबकि हमके पास 16.16 फीसदी आदिवासी हिंदीकारी हिस्सेदारी है। भारतीय जीवन बीमा निगम के पास 5.11 फीसदी समता का अधिकार है। अन्य बीमा कंपनियों व म्यूचुअल फंडों के पास 4 फीसदी से ज्यादा संतित अधिकार है, वहीं सुदना निवेशकों के जत्थे के पास 8.55 फीसदी वोटिंग अधिकार है।



IIM Lucknow
INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT LUCKNOW

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMES FEBRUARY 2017

ADVERTISEMENT THAT WORKS
Programme Director: Prof. Alekhan Chakravarty, February 2-8, 2017 at Noida campus.
This programme equips participants with the concepts and application of advertisement principles which has a burning as well as effective and effective communication value.

MANAGERIAL EFFECTIVENESS
Programme Director: Prof. Archana Shukla, February 6-10, 2017 at Lucknow campus.
The primary objective of this programme is to help participants understand the roles and functions of a manager, and build the requisite competencies and skills to perform the role effectively. More specifically the programme would focus on self-understanding, interpersonal effectiveness, communication, time management and planning, team building and decision making, leadership and managerial styles, performance management (counseling and appraisal), and strategy in work and result orientation.

PREDICTIVE ANALYTICS FOR BUSINESS DECISION MAKING
Programme Director: Prof. Pradeep Kumar, February 6-10, 2017 at Lucknow campus.
The primary objective of this programme is to understand the role of predictive analytics, business intelligence, and big data within and outside organization; analyse data using statistical and data mining techniques to discover the hidden and apply the gained knowledge in business; applications of Decision support systems tools and techniques; role of data warehousing and OLAP; frameworks covering CRM strategy; and covers in Data Mining techniques like Association rule, Clustering, Classification in CRM framework like RFM, CRC, use analytics in customer relationship management, banking and finance, fraud detection, sentiment analysis.

SERVICE EXCELLENCE FOR FIRM PROFITABILITY
Programme Director: Prof. Anirban Chakraborty, February 8-11, 2017 at Lucknow campus.
This course equips participants with the concept and application of tools in marketing for achieving excellent customer experiences through managing and assessing customer expectations from the perspective of product, process, people, place, technology and customer service standards.

FINANCE FOR DECISION MAKING (FOR NON-FINANCE EXECUTIVES)
Programme Directors: Prof. Prakash Singh & Prof. Vikas Srivastava, February 13-17, 2017 at Lucknow campus.
The primary objective of this programme is to provide the managers with a comprehensive working knowledge of critical financial principles in an easy to follow manner that will help them make better decisions. The participants will be able to communicate finance related matters more effectively, understand the performance metrics of the organization, read and use company reports and comprehend other managerial accounting aspects. They will learn to interpret crucial financial data in ways that would lead to improve their effectiveness and initiate and contribute in corporate discussion.

COACHING AND MENTORING FOR EFFECTIVE LEADERSHIP
Programme Director: Prof. Sushil Kumar & Prof. Bhamaris Ahirao, February 16-18, 2017 at Noida campus.
The primary objective of this programme is to help participants in the process of Self and Role; to appraise the participants to various issues involved in Personal Growth and Effectiveness; to make the participants aware of their Strong Be and Areas of Potential Development; to provide him to hone various skills, and to provide opportunity to Observe, Experiment and Practice new behaviours in supportive environment.

INTERPERSONAL COMMUNICATION SKILLS, PRESENTATION SKILLS AND IMAGE MANAGEMENT
Programme Director: Prof. Payal Bishnu, February 22-24, 2017 at Lucknow campus.
The primary objective of this programme is to offer effective, thought provoking and interactive sessions that address specific and unique issues related to communication. It provides a menu for the participants, as it is only through models, self-awareness that we can understand ourselves and others. The workshop also demonstrates the value of listening or accepting in the process as well as of action for better communication and relationship results.

EFFECTIVE COMPLIANCE MANAGEMENT FOR BUSINESS ADVANTAGE
Programme Director: Prof. Dhananjay S Sarpe, February 23-25, 2017 at Noida campus.
The primary objective of this programme is to develop skills necessary to create a compliance culture and provide a comprehensive compliance programme within the organization; to develop ability to conduct the Compliance Risk Profiling of an organization; to develop ability to identify, assess and address the compliance/regulatory challenges of the organization and devise counter strategies to overcome them; To develop skills for effective Compliance Communication and Compliance Audit; to develop an attitude to understand and appreciate the regulatory/ compliance obligations and its implementation, and to develop a confidence to handle the compliance issues more effectively and proactively for competitive business advantage.

SOCIAL MEDIA MARKETING AND SOCIAL MEDIA ANALYTICS
Programme Director: Prof. Abhishek Kaushik, February 27 – March 1, 2017 at Noida campus.
The primary objective of this programme is to understand the evolving nature of social media marketing; Understand the processes involved in developing a social media marketing plan; Gain an understanding of tools and methods for social media analytics; Comprehend the strategic role of social media marketing (e.g., customer relationship management, reputation management); and return, to the workplace with actionable ideas in all areas of social media marketing including specific tools and platforms.

For details, please visit http://www.iiml.ac.in/edp/call or write to Programme Manager (MDP)
Indian Institute of Management Lucknow
Prabandh Nagar, Off Road, Lucknow 226 013
Phone: 0522-4096282, 96, 84, 45
Fax: 0522-2734026/6; E-mail: mdpoffice@iiml.ac.in; mdp@iiml.ac.in

THE KARNATAKA BANK LIMITED

Our Bank was incorporated on February 18, 1924 as The Karnataka Bank Limited under the Indian Companies Act, 1913. The certificate of commencement of business was obtained on May 03, 1924. Our Bank received declaration to carry on the banking business of banking under Banking Regulation Act, 1949, from the Reserve Bank of India on April 1, 1966.
Registered Office: P.B. No. 599, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangalore, 575 002, Karnataka. Contact Person: Mr. V.V. Raghavendra, Company Secretary and Compliance Officer. Telephone: +91 (824) 2228100-04. Facsimile: +91 (824) 2225688. Email: corpsec@ktkbank.com. Website: www.karnatakabank.com
Corporate Identity Number: L85110KA1924PLC001128

PROMOTERS: Our Bank has no identifiable promoters

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE KARNATAKA BANK LIMITED (OUR "BANK" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 8,42,35,491 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR BANK FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 10 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 0 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ 699.65 CRORE ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR BANK IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDER ON THE RECORD DATE, THAT IS, OCTOBER 25, 2016 ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IS SEVEN TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 92 OF THE LETTER OF OFFER ("LOF")
READ WITH ADDENDUM CUM CORRIGENDUM DATED NOVEMBER 19, 2016. THE ENTIRE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS PAYABLE ON APPLICATION

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Bank thanks all the investors for their response to the Issue, which opened for subscription on November 7, 2016 and closed on November 28, 2016. Indented from November 21, 2016 through an addendum cum corrigendum dated November 19, 2016. The total number of Composite Application Forms ("CAFs") and Plain Paper Applications (together referred as "Applications") received were 65,717 for 17,48,22,791 Rights Equity Shares which is 185.92% of the Issue size in terms of number of Rights Equity Shares applied for. The Basis of Allotment was finalized on December 7, 2016 in consultation with the BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange. The Basis of Allotment has been approved by the Board of Directors on December 8, 2016 and 8,41,36,848 Rights Equity Shares have been allotted. All valid Applications including those submitted through Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") have been considered for allotment.

1. The break-up of valid Applications (including ASBA Applications) is given below:

Category	No. of Valid Applications (including ASBA applications) received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Shareholders	52,808	7,87,36,991	1,53,91,929	9,41,28,920
Renunciees	2,856	27,27,580		27,27,580
Total	55,664	7,88,29,840	1,53,91,929	9,41,36,848*

*Out of the total issue size of 8,42,35,491 Rights Equity Shares, 98,573 Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications		Rights Equity Shares Applied for		Rights Equity Shares Allotted	
	Number	%	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Shareholders	52,180	80.40	17,13,76,949	97.99	9,24,28,299	3,39,36,10,220	97.15
Renunciees	2,841	4.38	34,91,792	2.01	27,27,580	10,10,10,600	2.85
Total	64,717*	100.00	17,48,22,791	100.00	9,41,36,848	3,49,46,80,820	100.00

*Under ASBA process, four shareholders had submitted 10 Applications each with same CAFs number, which have been grouped and considered as 'one' valid Application. Thus the total number of Applications received stands at 65,717 (64,717-4+4).

Out of the total 65,717 Applications (including 11,189 ASBA Applications) received, 261 CAFs (including 100 ASBA Applications) for 3,10,770 Rights Equity Shares (including 2,16,338 Rights Equity Shares applied under ASBA process) were rejected on technical grounds.

Dispatch / Refund Orders: The refund instructions to SCSBs for unblocking of funds, was given on December 8, 2016. The dispatch of allotment advice, cum refund orders, allotment advice cum refund letter/letter of regret and physical share certificates of the Bank, as applicable, have been completed on December 9 and 10, 2016. The Company has sent the letter / applications with the BSE Limited ("BSE") and with the National Stock Exchange of India Ltd ("NSE") on December 9, 2016. The credit in respect of Rights Equity Shares in dematerialized form to the respective demat accounts of the investors with National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, was completed on December 9, 2016. The Rights Equity Shares shall commence trading on BSE and NSE with effect from December 14, 2016, pursuant to their letters, and trading will be permitted only in dematerialized form in the demat segment of the stock exchanges only for Banks.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE SECURITIES OF OUR BANK CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALIZED FORM.

No Offer in the United States

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act, or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred on or within the United States of America or on the territories or possessions thereof ("United States" or "U.S."), or to, or for the account or benefit of "U.S. persons" (as such term is defined in Regulation S of the Securities Act), except pursuant to a transaction exempt from the registration requirements of the Securities Act. The Offering in which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or as a solicitation thereof or an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlements. There will be no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the LOF / Abridged Letter of Offer ("the LOF") and the CAF will not be sent to any U.S. person and should not be forwarded or transmitted in any form or manner, and neither, and the rights in ATS or any other form or manner in the United States. Any offer for sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares within the United States (or to a dealer (whether or not it is a participating in the Issue) may violate the registration requirements of the Securities Act.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on page 83 of this LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by BSE Limited nor does it warrant that the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 83 of this LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE nor does it warrant the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of NSE" on page 83 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE RBI: A license authorizing our Bank to carry on banking business has been obtained from the RBI in terms of Section 22 of the Banking Regulation Act. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the RBI does not undertake any responsibility for the financial soundness of our Bank.

All capitalized terms used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the LOF dated October 28, 2016 read with Addendum cum Corrigendum dated November 19, 2016. Any correspondence in respect of allotment to Registrar & Equity Shares, pertaining to the Issue may be addressed to the Registrar to the Issue at the address mentioned below.

Lead Manager to the Issue	Registrar to the Issue	Company Secretary & Compliance Officer
Edelweiss Edelweiss Financial Services Limited 14th Floor, Edelweiss House Off C.S.T. Road, Kalina Mumbai 400 098 Telephone: +91 (22) 4009 4400 Facsimile: +91 (22) 4086 3610 E-mail: ibd.rights@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Contact Person: Mr. Vimal Shah / Mr. Vaibhav Shah SEBI Registration No.: INM0000010650	Integrated Integrated Enterprises (India) Limited No. 30 Ramana Residency, 4th Cross Sampige Road, Malleswaram Bengaluru 560 003 Telephone: + 91 (80) 23460815-818 Facsimile: + 91 (80) 23460819 E-mail: karnataka@integratedindia.in Investor Grievance E-mail: bir@integratedindia.in Website: www.integratedindia.in Contact Person: Mr. T. Vasudevan / Mr. K. I. Sheriff SEBI Registration No.: INR000000544	Mr. V.V. Raghavendra, Company Secretary and Compliance Officer P.B. No. 599, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangalore, 575 002 Telephone: +91 (824) 2228100-04, Facsimile: +91 (824) 2225688 Website: www.karnatakabank.com, E-mail: corpsec@ktkbank.com Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-issue/ post-issue related matters such as non-receipt of letter of Allotment, credit of Rights Equity Shares, Refund Orders or refund through electronic credit and such other matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE BANK.

For The Karnataka Bank Limited,
Sd/-
V.V. Raghavendra
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mangalore
Date: December 13, 2016

Advertisement

HIT BY MANPOWER CRISIS

CBDT seeks to enlist I-T officers in its probe team

DILASHA SETH
New Delhi, 13 December

Facing a 'serious' manpower crunch to investigate fraudulent and 'serious irregularities' on account of demonetisation, Central Board of Direct Taxes (CBDT) chairman Sushil Chandra has in an internal letter sought to rope in income tax inspectors to assist the investigation team.

In the letter, reviewed by Business Standard , addressed to all principal chief commissioners, Chandra has highlighted that the investigation team was 'seriously handicapped' due to manpower shortage.

"Investigation Directorates have intensified enforcement actions in detecting serious irregularities. They are, however, seriously handicapped because of non-availability of manpower," the CBDT chief said in the letter.

He added that the current investigation and enforcement drive was likely to continue in the coming weeks.

Chandra recommended reorganisation of work by the field formations, which could spare a few officers for investigation. He asked the principal chief commissioners to identify such officers and income tax inspectors and 'make them available to the Directors



READY FOR SOME ACTION

- While the income tax department has a sanctioned strength of about 60,000, about 15,000 are part of the investigation team
- There are 9,490-odd income tax inspectors, who only assist the income tax officers or joint commissioners to carry out assessment
- Now, these inspectors are likely to report to the investigation team

General of Income Tax (Investigation), or DGIT (Inv).

While the income tax department has a sanctioned strength of about 60,000, about 15,000 are part of the investigation team. There are 9,490-odd income tax inspectors, who only assist the income tax officers or joint commissioners to carry out assessment. But now, these inspectors will likely report to the investigation team. There are 14 Director Generals under DGIT (Investigation) — Ahmedabad, Bengaluru, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow, Mumbai, New Delhi, Patna and Pune.

The DGIT (Inv) is the revenue enforcement agency of the CBDT. The two income tax associations — Income Tax Employees Federation and the Income Tax Gazetted Officers' Association — in a letter to Prime Minister Narendra Modi said that they were "totally demotivated due to huge shortage of manpower". They pointed out that there are 30-35 per cent of vacancies at 'cutting-edge positions' like Additional Commissioner of I-T and Deputy Commissioner of I-T, their junior ranks and others.

The investigation department of income tax has cracked down on the number of money laundering and gold rackets operating across the country, fraudulently converting black money into white for a commission since the legal tender of ~500 and ~1,000 notes was withdrawn.

The income tax sleuths have nabbed offenders and recovered cash worth several crores in crackdowns in various parts of the country including Mumbai, Ahmedabad and Nagpur.

Since November 8, the department has detected more than ~1,500 crore of undisclosed income during surveys and searches and around ~120 crore has been seized so far.

After investigation wing, the spotlight will likely turn to the assessment officers. According to the sanctioned strength of the income tax department, there are 7,294 assessment officers up to the additional commissioner's level, which includes 4,204 income tax officers who assess returns filed by taxpayers. The additional commissioners and joint commissioners handle 30-40 quality cases a year, while the income tax officers assess 100-150 cases a year, but smaller ones.

Banks asked to do central data checking: RBI on laundering

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, 13 December

With more and more instances of money laundering and fraudulent currency exchange surfacing, the Reserve Bank of India (RBI) on Tuesday warned of stern action against wrongdoers and asked banks to carry out a thorough central data checking, while it suspended a "junior functionary" who is being investigated.

"We have issued elaborate instructions to all banks to do the central data checking and wherever they find any inconsistency, it should be pursued further through their internal audit mechanism," said deputy governor of RBI, S S Mundra, speaking to a select group of reporters here.

"Our supervisors are also carrying out similar exercise on various data points of banks and wherever any untoward kind of transactions or actions are noticed, due action would be pursued and due investigation would be carried out," he said.

He denied the reports that RBI had issued show-cause notice to Axis Bank and was planning to cancel its banking licence following massive malpractices in currency exchange at many of its branches.

> "We have issued elaborate instructions to all banks to do the central data checking and wherever they find any inconsistency, it should be pursued further through their internal audit mechanism"
>
> S S MUNDRA
> RBI deputy governor

"There is no such thing at this point of time. As I mentioned a while ago, wherever any such actions are reported, the enquiries are being made but as of now no show-cause notice has been issued (to Axis Bank)," Mundra said. Stating that many instances of money-laundering have come to the RBI's notice, he said already banks have taken action against the staff who were involved.

About the arrest of an RBI official in Bengaluru earlier on Tuesday, Mundra said: "Let me clarify it is a junior functionary of RBI and it was reported by the investigating agency that he was recorded to be present in a bank branch where this kind of transaction was happening. We have suspended the employee and have instituted investigation and due action will be taken once the details are known."

ACQUISITION / BUYOUTS

We are looking to take majority shareholding (or 100% buyouts) in running, profitable SMEs. Ideal targets would be businesses with no succession plans.

Desired Criteria:

- **Revenues:** Revenues: Between INR 30 – 100 crores. Preference for high margin, high ROE businesses with strong growth potential.
- **Sectors:** Financial Services, Business Services, Media, Consumer Products, and Food
- **Operating locations:** Mumbai, Delhi, Pune, Bangalore and Hyderabad

Contact Details: smebuyouts@gmail.com

Just4u Financial Services Pvt. Ltd. has roped in senior bankers from cooperative sector and private banks. They have been rapidly increasing their reach across India. Just4u financial services Pvt Ltd is working on a unique concept wherein it assist the borrower to choose from host of banks , NBFC , private lenders the right mix in terms of borrowing through fund based and non fund based combination. At present only Just4u loan caters to this kind of service in an organised manner across India. As per Jayesh Kala, director Just4u Financial Services Pvt. Ltd. due to demonetisation banks across country are flush with deposits, these change of situation will have multifold impact on the economy. On one side due to excess liquidity in the system banks will tend to reduce rate of deposit and on other side banks will have to lend aggressively to cope up with additional interest outgo due to increase in deposits. However in light of mounting bad loans and slow pace of industrial growth, it will be interesting to understand as to which sector banks will be focussing on for lending. In the past the banks have already burnt their fingers heavily due to delinquencies by big corporate houses. It appears banks will shift their attention to SME traders and manufacturers for increased lending as their default ratio is less as compared to big corporates, also the lending to SME segment will have the risk spread over number of borrowers thereby reducing the chances of spurt in NPA if eventually loan goes bad. Just4u loan will have added advantage in this current scenario post demonetisation since their focus is on SME segment. Given their wide network and experience of the promoters and team of highly talented retd bankers and professionals Just4u financial services Pvt ltd shall be most preferred by the potential borrowers to guide them on the right mix of loan which will enable them to reduce their cost of borrowings. Simultaneously banks will also prefer to lend to borrowers whose paperwork is upto mark as per the criteria of banks.

Oil firms, railways to stump up ~2,425-crore cashless freebies

SHINE JACOB & ARUP ROYCHOUDHURY
New Delhi, 13 December

If sale of petrol and diesel becomes cashless, state-run oil companies will shoulder a yearly burden of ~2,400 crore because of the 0.75 per cent discount offered. The railways will bear ~25.2 crore for offering free insurance to passengers buying tickets online.

Sources said when Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation and Hindustan Petroleum Corporation announced the rebate on Tuesday night, the government had not issued formal instructions to them.

Finance Minister Arun Jaitley had on December 8 announced a 0.75 per cent discount for cashless purchase of petrol and diesel. He did not say who would pay for it.

A finance ministry official said the central government would not absorb the discounts for cashless transactions and these would be borne by public sector insurance and oil companies and the railways.

"When you buy insurance online, you eliminate the agent. The amount you save can bear the cost of these discounts. The burden will be very small," the official said. The discounts are not temporary because the government wants to nudge people towards online transactions, according to another official. Petrol and diesel worth ~1,800 crore are bought daily in the country and 20 per cent is normally paid for by digital means. This share zoomed to 40 per cent in November and ~360 crore of transactions shifted to cashless methods.

> Petrol and diesel worth ~1,800 cr are bought daily in the country

"This (the discount) is likely to shift at least 30 per cent more customers to digital means, which will reduce the cash requirement by nearly ~200,000 crore a year at petrol pumps," the official added. Of the 53,000 petrol pumps fed by state-run oil companies, only 30,000 have card swiping machines. The oil companies have sought over 23,000 machines from banks in an effort to go completely digital. "Due to a rise in crude oil prices, diesel is likely to become dearer by ~1.4 a litre and petrol by ~1.6 a litre. Oil companies are likely to adjust the losses from the cashless drive against these hikes," said a Mumbai-based analyst who did not wish to be named.

Indian Railway Catering and Tourism Corporation may have to spend ~25.2 crore to provide free insurance to customers who buy tickets online. "For the time being, IRCTC will absorb it. The cost will come to around 70 paise per ticket," said a railway official.

The railway subsidiary may also have to absorb the 5 per cent discount for catering, accommodation and retiring rooms to customers paying online.

Opposition and govt prepare for note ban slugfest until Dec-end

ARCHIS MOHAN & AMIT AGNIHOTRI
New Delhi, 13 December

While the remainder of the winter session of Parliament, which concludes on Friday, is set for a washout, Opposition parties believe they have two weeks, that is until the New Year's Eve, to build a nationwide narrative against Narendra Modi government's 'note ban' decision.

The Modi government and the Bharatiya Janata Party (BJP) are biding their time until December 31, the scheduled end of the demonetisation exercise, after which the PM is likely to unveil sops for the poor. In the interregnum, the BJP plans to counter the Opposition propaganda by attacking the Congress-led UPA for its multitude of scams. On Tuesday, Finance Minister Arun Jaitley said high-denomination notes, as percentage of total currency in circulation, increased from a mere 36 per cent to over 80 per cent during UPA regime, that is from 2004 to 2014. Jaitley's was a reference to alleged ill-gotten money from the scams being hoarded in high denomination currency notes. The Opposition, comprising 17 political parties with the Congress in the lead, will have a meeting at the end of the winter session to strategise a common theme for their protests across the country until December 31. The protests and awareness campaigns against 'note ban' will focus on three issues — job losses in the informal sector, how 'note ban' is a "grand scam" to benefit select industrialists and allegations that BJP state units had advance information, which helped them convert their unaccounted money into 'white' money.



Congress Vice-President Rahul Gandhi addressing the traders, wholesalers and workers at Anaj Mandi in Dadri, UP on Tuesday PHOTO: PTI

Some of the opposition parties, particularly the Trinamool, are aware of the Achilles' Heel of the Congress on corruption, and have insisted that a united Opposition should instead shift the discourse to the human suffering because of 'note ban'.

In a show of unity, Rashtriya Lok Dal leader Ajit Singh will hold a public rally in Muzaffarnagar on December 22 and has invited several leaders of other opposition parties, including the Trinamool and Nationalist Congress Party.

According to Congress and Trinamool leaders, the unity among 17 opposition parties needs to be taken to the streets. "As the principal opposition party, the Congress already demonstrated that leadership role in Parliament. We will initiate groundwork for joint nationwide protests against demonetisation outside Parliament," Congress veteran Satyavrat Chaturvedi said. Coordination with regional players in the states has been left to the respective state Congress units.

The Congress has planned that its leaders will visit areas and sectors that have suffered the most "pain". On Tuesday, Congress Vice-President Rahul Gandhi visited the Dadri grain market in Western Uttar Pradesh. Senior Congress leader P Chidambaram addressed a press conference in Nagpur. In Vijayawada, Communist Party of India (Marxist) chief Sitaram Yechury said note ban was a huge scam.

The Congress units in Delhi and Mumbai have started holding public meetings dubbed as "note pe charcha" over the issue. The Trinamool also started a three-day block level campaign in Bengal to highlight the impact of note ban on the state's leather, jute and tea industries. Bengal CM Mamata Banerjee has taken to tweet against 'note ban' in Hindi. Trinamool Congress MP Derek O'Brien said Banerjee was the first to visit a wholesale vegetable market in Delhi to highlight the 'note ban' impact. "The real estate sector is badly hit. Ludhiana's hosiery mills have suffered job losses. Informal sector workers have either not received wages or lost their jobs. Our party will highlight this," he said.

The winter session of Parliament, which will resume after a four-day break on Wednesday, is unlikely to transact any business in the last three days of the session that concludes on Friday.

This is only an advertisement for information purposes and not for publication or distribution directly or indirectly outside India and not for distribution to, or for the account or benefit of, any U.S. person (as defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933, as amended) or in or into the United States of America. This is not an announcement for the offer document.

THE KARNATAKA BANK LIMITED

Our Bank was incorporated on February 18, 1924 as The Karnataka Bank Limited under the Indian Companies Act, 1913. The certificate of commencement of business was obtained on May 23, 1924. Our Bank received a license to carry on the banking business in India under the Banking Regulation Act, 1949, from the Reserve Bank of India on April 4, 1966.
Registered Office: P.B. No. 599, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangaluru 575 002, Karnataka; **Contact Person:** Mr. Y.V. Balachandra, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 (824) 2226182-4; **Facsimile:** +91 (824) 2225566; **Email:** comsec@ktkbank.com; **Website:** www.karnatakabank.com; **Corporate Identity Number:** L85110KA1924PLC001128

PROMOTERS: Our Bank has no identifiable promoters

FOR PRIVATE CIRCULATION TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF THE KARNATAKA BANK LIMITED (OUR "BANK" OR THE "ISSUER") ONLY

ISSUE OF UP TO 9,42,35,441 EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR BANK FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 70 PER RIGHTS EQUITY SHARE ("ISSUE PRICE") INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 60 PER RIGHTS EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ 659.65 CRORE ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBLE SHAREHOLDERS OF OUR BANK IN THE RATIO OF 1 (ONE) RIGHTS EQUITY SHARES FOR 2 (TWO) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES HELD BY SUCH ELIGIBLE SHAREHOLDER ON THE RECORD DATE, THAT IS, OCTOBER 25, 2016 ("ISSUE"). THE ISSUE PRICE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES IS SEVEN TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 92 OF THE LETTER OF OFFER ("LOF") READ WITH ADDENDUM CUM CORRIGENDUM DATED NOVEMBER 19, 2016. THE ENTIRE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS PAYABLE ON APPLICATION.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of our Bank thanks all the investors for their response to the Issue, which opened for subscription on November 7, 2016 and closed on November 28, 2016 (extended from November 21, 2016 through an addendum cum corrigendum dated November 19, 2016). The total number of Composite Application Forms ("CAFs") and Plain Paper Applications (together referred as "Applications") received were 65,771 for 17,48,22,711 Rights Equity Shares which is 185.52% of the Issue size in terms of number of Rights Equity Shares applied for. The Basis of Allotment was finalized on December 7, 2016 in consultation with the BSE Limited ("BSE"), the Designated Stock Exchange. The Basis of Allotment has been approved by the Board of Directors on December 8, 2016 and 9,41,36,866 Rights Equity Shares have been allotted. All valid Applications (including Application Supported by Blocked Amount ("ASBA")) have been considered for allotment.

1. The break-up of valid Applications (including ASBA applications) is given below:

Category	No. of Valid Applications (including ASBA applications) received	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares accepted and allotted against Additional applied (B)	Total Rights Equity Shares accepted and allotted (A+B)
Shareholders	62,609	7,80,98,360	1,53,10,926	9,14,09,286
Renouncees	2,895	27,27,580	–	27,27,580
Total	65,504	7,88,25,940	1,53,10,926	9,41,36,866*

*Out of the total Issue size of 9,42,35,441 Rights Equity Shares, 98,575 Rights Equity Shares have been kept in abeyance.

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications		Rights Equity Shares Applied for			Rights Equity Shares allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Shareholders	62,780	95.45	17,13,15,949	11,99,22,10,930	97.99	9,14,09,286	6,39,86,50,020	97.10
Renouncees	2,991	4.55	35,06,762	2,45,473,340	2.01	27,27,580	19,09,30,600	2.90
Total	65,771#	100.00	17,48,22,711	12,23,76,84,270	100.00	9,41,36,866	6,58,95,80,620	100.00

#Under ASBA process, four shareholders had submitted 10 Applications with same CAFs number, which have been grouped and considered as 4(four) valid Applications. Thus the total number of Applications received reduced from 65,777 to 65,771.

Out of the total 65,771 Applications (including 11,150 ASBA Applications) received, 267 CAFs (including 100 ASBA Applications) for 3,13,773 Rights Equity Shares (including 2,16,138 Rights Equity Shares applied under ASBA process) were rejected on technical grounds.

Dispatch / Refund Orders : The refund instructions to SCSBs for unblocking of funds, was given on December 8, 2016. The dispatch of allotment advice cum refund orders, allotment advice cum refund intimation and physical share certificates to the Allottees, as applicable, have been completed on December 9 and 10, 2016. The Company has filed the listing applications with the BSE Limited ("BSE") and with the National Stock Exchange of India Ltd. ("NSE") on December 8, 2016. The credit in respect of allotment of Rights Equity Shares in dematerialized form to the respective demat accounts of the investors with National Securities Depository Limited and Central Depository Services (India) Limited, was completed on December 9, 2016. The Rights Equity Shares shall commence trading on BSE and NSE with effect from December 14, 2016, pursuant to their listing and trading approval and shall be traded with the same ISIN INE614B01018, as the existing equity shares.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE SECURITIES OF OUR BANK CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

No Offer in the United States

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the Securities Act, or any U.S. state securities laws and may not be offered, sold, resold or otherwise transferred within the United States of America or the territories or possessions thereof ("United States" or "U.S."), or to, or for the account or benefit of "U.S. persons" (as defined in Regulation S of the Securities Act), except in a transaction not subject to, or exempt from the registration requirements of the Securities Act. The offering to which the LOF relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlement for sale in the United States or as a solicitation therein of an offer to buy any of the Rights Equity Shares or Rights Entitlement. There is no intention to register any portion of the Issue or any of the securities described herein in the United States or to conduct a public offering of securities in the United States. Accordingly, the LOF / Abridged Letter of Offer ("ALOF") and the CAFs should not be forwarded to or transmitted in or into the United States at any time. In addition, until the expiry of 40 days after the commencement of the Issue, an offer or sale of Rights Entitlements or Rights Equity Shares within the United States by a dealer (whether or not it is participating in the Issue) may violate the registration requirement of the Securities Act.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of SEBI" on page 83 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not, in anyway, be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by BSE Limited; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer Clause of BSE" on page 87 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the LOF has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the LOF. The investors are advised to refer to the full text of the "Disclaimer clause of NSE" on page 88 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF THE RBI: A license authorising our Bank to carry on banking business has been obtained from the RBI in terms of Section 22 of the Banking Regulation Act. It must be distinctly understood, however, that in issuing the license the RBI does not undertake any responsibility for the financial soundness of our Bank.

All capitalised terms used but not defined herein shall have the meanings assigned to them in the LOF dated October 28, 2016, read with Addendum cum Corrigendum dated November 19, 2016. Any correspondence in respect of allotment of Rights Equity Shares pertaining to the Issue may be addressed to the Registrar to the Issue at the address mentioned below.

Lead Manager to the Issue	Registrar to the Issue	Company Secretary & Compliance Officer
Edelweiss Financial Services Limited 14th Floor, Edelweiss House, Off C.S.T. Road, Kalina, Mumbai 400 098 Telephone: +91 (22) 4009 4400; Facsimile: +91 (22) 4086 3610 E-mail: kbl.rights@edelweissfin.com Website: www.edelweissfin.com Contact Person: Mr. Viral Shah / Mr. Vaibhav Shah SEBI Registration No.: INM0000010650	Integrated Enterprises (India) Limited No 30 Ramana Residency ,4th Cross, Sampige Road, Malleswaram, Bengaluru 560 003 Telephone: + 91 (80) 23460815-818; Facsimile: + 91 (80) 23460819 E-mail: vijayagopal@integratedindia.in Investor Grievance E-mail: blr@integratedindia.in Website: www.integratedindia.in Contact Person: Mr. S. Vijayagopal/ Mr. E.T Balaji SEBI Registration No: INR 000000544	Mr. Y V Balachandra, Company Secretary and Compliance Officer P.B. No. 599, Mahaveera Circle, Kankanady, Mangaluru 575 002 Telephone: +91 (824) 2226182/3/4; Facsimile: +91 (824) 2225566 Website: www.karnatakabank.com; E-mail: comsec@ktkbank.com Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/ post-Issue related matters such as non-receipt of letter of Allotment, credit of Rights Equity Shares, Refund Orders or refund through electronic credit and such other matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Rights Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE BANK.

For The Karnataka Bank Limited,
Sd/-
Y.V. Balachandra
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mangaluru
Date: December 13, 2016

Adfactors 377

ಒಡಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ದತ್ತ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ, ದತ್ತ ಮಹಾಯಾಗ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾಪನ

ಆತ್ಮನಿಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀಡಿದ್ದು ದತ್ತಾತ್ರೇಯರು: ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ



ಬೋಳಾರ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ

ಡಿ. 15-19: ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ



ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ನಾಳೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ





ಮಿಸ್ ಸುಪ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಹುಟ್ಟೂರ ಸಮ್ಮಾನ

ಶ್ರೀನಿಧಿ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆ: ಸಂಸದ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್

ಆರ್‌ಬಿಐ ನೀತಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ: ಡಾ| ಎಂ.ಎನ್.

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ



ಭಾರತೀಯ ವಿಕಾಸ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರಕುಶಲ ತರಬೇತಿ

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ,

THE KARNATAKA BANK LIMITED

PROMOTERS: Our Bank has no identifiable promoters

BASIS OF ALLOTMENT

Business Standard

Business Standard Private Limited,
H/3&4 Paragon Centre,
Opp. Century Mills, P. B. Marg,
Worli, Mumbai - 400 013.
Tel. : 91-022-2497 8456
Fax : 022-2497 8539
email : bs.legal@bsmail.in
CIN : U00000DL1970PTC100242

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify that the advertisement has been published from Adfactors Advertising Agency for their client The Karnataka Bank Ltd. on 14.12.2016 in our Business Standard English(Mumbai, Pune, Ahmedabad, Kochi, Banglore, Chennai, Hydrabad, Delhi, Chandigarh, Lucknow, Kolkattta, Bhubaneshwar, Bhopal) & Hindi(Mumbai, Delhi, Chandigarh, Lucknow, Kolkatta, Bhopal, Patna, Raipur) Editions.

Regards,

Kushal Chaudhary
Business Standard Pvt Ltd.